

माँब लचिगि

प्रलिमिंस के लयि:

[भारतीय न्याय संहति \(BNS\), 2023, NCB, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामला 2018](#)

मेन्स के लयि:

माँब लचिगि और धार्मिक कट्टरवाद: चुनौतियाँ और आगे की राह

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए माँब लचिगि (भीड़ द्वारा हत्या) और **गौ-रक्षा के नाम पर** हिसा के मामलों में मुआवजे के रूप में एक समान राशति तथा नगिरानी के लयि राष्ट्रव्यापी नरिदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।

- हालाँकि, इसने पुनः पुष्टि की कि उसके वर्ष 2018 के तहसीन पूनावाला दशा-नरिदेश संविधान के [अनुच्छेद 141](#) के तहत सभी राज्यों के लयि बाध्यकारी है।

माँब लचिगि क्या है?

परचिय:

- माँब लचिगि एक सामूहिक हिसा है, जिसमें एक समूह कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, कथति गलत कार्य के आधार पर व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से दंडति करता है।
- माँब लचिगि (भीड़ द्वारा हत्या) सामूहिक हिसा का एक रूप है, जिसमें एक समूह द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कथति अपराधों के लयि लोगों को अवैध रूप से दंडति किया जाता है।
- गौ-रक्षा के नाम पर की जाने वाली हिसा, धर्मनरिपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के लयि खतरा है, जो प्रायः संदेह से प्रेरति होती है।

माँब लचिगि के कारण:

- सांस्कृतिया पहचान के लयि कथति खतरा: लचिगि तब होती है जब किसी व्यक्तिया समूह को सांस्कृतिक, धार्मिक या पारंपरिक मूल्यों के लयि खतरा माना जाता है।
 - सामान्य कारणों में अंतरजातीय/अंतरधार्मिक संबंध, खान-पान की आदतें, या सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले रीति-रिवाज शामिल हैं।
- फेक न्यूज़: फेक न्यूज़, जो अक्सर सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैलाई जाती हैं, माँब लचिगि में योगदान दे सकती हैं।
- सामाजिक-राजनीतिक तनाव: भूमि विवाद, संसाधन प्रतस्पर्द्धा और आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न तनाव हिसा में बदल सकता है, जिसका अक्सर राजनीतिक लाभ के लयि शोषण किया जाता है।
- सांप्रदायिक विभाजन: ऐतिहासिक धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक तनाव अक्सर लचिगि की घटनाओं के लयि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
- नैतिक सतर्कता: स्वघोषति संगठन सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी धारणा को कायम रखने के लयि हिसा का प्रयोग करते हैं, वशिष रूप से उन लोगों को नशाना बनाते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनका उल्लंघन कर रहे हैं।

भारत में माँब लचिगि से संबंधति वधिकि प्रावधान क्या हैं?

भारतीय न्याय संहति (BNS), 2023:

धारा 103(2): माँब लचिगि

- जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मलिकर नसल, जाति, समुदाय, लैंगिक हिसा, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तित्व वशिवास के

आधार पर हत्या करता है।

- सज़ा: मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना।

○ धारा 117(4): भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुँचाना

- जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मलिकर समान भेदभावपूर्ण आधार पर गंभीर चोट पहुँचाता है।

- सज़ा: 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

■ **2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लचिगी की कड़ी नदि करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता।

- न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनर्थांतरि लचिगी "नई सामान्य बात" बन सकती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभ्य समाज में भीड़ द्वारा न्याय का कोई स्थान नहीं है।

- इसमें कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा करना तथा लक्ष्ति हिसा को रोकना राज्य का कर्तव्य है।

- इसने अमेरिकी कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर बल दिया कि भीड़ द्वारा न्याय, वधिके शासन को कमज़ोर करता है।

○ मॉब लचिगी के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- उकसावे के खिलाफ सख्त कार्रवाई: घृणास्पद भाषण या फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ IPC की धारा 153A(BNS में धारा 196) के तहत (वभिन्नि समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के लिये) स्वतः FIR दर्ज़ की जाएगी।

■ नविरक उपाय: राज्य प्रत्येक ज़िले में एक वरषिट पुलसि अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नयुक्त करेंगे। इसमें

- संवेदनशील कषेत्रों की पहचान करना और पुलसि गश्त बढ़ाना, एवं

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अभद्र भाषा तथा फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना शामिल है।

■ दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय: प्रत्येक ज़िले में फास्ट-ट्रैक अदालतें 6 माह के भीतर मामलों का नपिटारा करेंगी।

- भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराधों के लिये आजीवन कारावास सहित कठोर सज़ा का प्रावधान।

- लापरवाह अधिकारियों के वरिद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।

■ पीड़ितों को मुआवज़ा: राज्यों को चोट की गंभीरता, आजीविका की हानि और चकितिसा व्यय के आधार पर मुआवज़ा हेतु योजना वकिसति करनी होगी।

■ अधिकारियों की जवाबदेही: लचिगी को रोकने में वफिल रहने वाले अधिकारियों के वरिद्ध कार्रवाई।

■ नगिरानी और वधायी उपाय: राज्यों को मॉब लचिगी की घटनाओं पर समय-समय पर रपिर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

- संसद से राष्ट्रीय स्तर पर लचिगी वरिधी कानून बनाने का आग्रह किया गया (यह लंबित है), हालाँकि राजस्थान और मणपुरि ने राज्य स्तर पर कानून बना लिये हैं।

मॉब लचिगी को रोकने में क्या चुनौतियाँ हैं?

■ वधिके खामियाँ और वधियों का अप्रभावी प्रवर्तन: भारत में लचिगी वरिधी कोई वरिषिट कानून नहीं है जिसके कारण ऐसे अपराधों के वरिद्ध कार्रवाई में बाधा आती है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लचिगी को रोकने के लिये दशिया-नरिदेश तय किये हैं लेकिन इनकप्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।

■ सांप्रदायिक भेदभाव और पक्षपात: लचिगी की घटनाओं से कमज़ोर समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं। इससे सांप्रदायिक वभिजन के साथ व्यवस्थागत भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण कानून प्रवर्तन के बारे में चिंताएँ बढ़ती हैं।

■ आँकड़ों की कमी और नीतगित खामियाँ: NCRB ने वर्ष 2017 के बाद से मॉब लचिगी और हेट क्राइम पर अलग-अलग आँकड़े दर्ज़ करना बंद कर दिया, जिससे इस मुद्दे की सीमा का आकलन करना जटलि हो गया और इस तरह की हिसा को रोकने के लिये प्रभावी उपाय तैयार करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

■ सोशल मीडिया और भ्रामक सूचना: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों से हिसा को बढ़ावा मलिता है, जिससे इनका वनियमन और जवाबदेहता मुश्कलि हो जाती है।

आगे की राह

■ राष्ट्रीय कानून: एकरूपता और नविरण के कर्म में कठोर दंड एवं त्वरति सुनवाई के साथ एक समरपति लचिगी वरिधी कानून आवश्यक है।

■ मज़बूत कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका: मॉब लचिगी को रोकने के साथ उसके संबंघ में जवाबदेहता सुनश्चिति करनी चाहिये।

- पीड़ितों के लिये त्वरति सुनवाई एवं न्याय सुनश्चिति करने के कर्म में वरिषि जाँच दल (SIT) और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की सुवधि प्रदान करनी चाहिये।

■ जन जागरूकता एवं मीडिया: सरकार एवं नागरिक समाज को जागरूकता तथा नैतिक पत्रकारिता के साथ फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाकर मॉब लचिगी को रोकने में भागीदारी करनी चाहिये।

■ प्रोद्योगिकी वनियमन एवं साइबर सुरक्षा: डिजिटल नगिरानी को मज़बूत करना, हेट स्पीच पर अंकुश लगाना तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना आवश्यक है।

■ सामुदायिक सहभागिता: सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के साथ मॉब लचिगी पर अंकुश लगाने के लिये शकियात नविरण तंत्र स्थापति करना चाहिये।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

Q. भारत में मॉब लचिगी, वधिके शासन तथा सामाजिक सद्भाव के लिये खतरा है। इसके कारणों का वरिषिण करने के साथ इस मुद्दे को हल करने हेतु वधिके

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mob-lynching-10>

